भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 561

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक

561. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री आलोक शर्मा

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीति आयोग की दसवीं शासी परिषद बैठक के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य विषय क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सूचना के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा घोषित पहल क्या हैं और इन पहलों का अपेक्षित प्रभाव क्या होगा?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क और ख): नीति आयोग की शासी परिषद (जीसी), जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं और जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल शामिल होते हैं, देश की प्रमुख प्राथमिकताओं के साझा दृष्टिकोण को तैयार करने के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग की दसवीं जीसी बैठक 24 मई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दसवीं जीसी बैठक का एजेंडा **'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047'** के व्यापक विषय पर आधारित था, जिसमें 'उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना - जनसांख्यिकीय

लाभांश का लाभ उठाना' पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो कि दिसंबर 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का भी विषय था। बैठक के विषयगत क्षेत्र थे (i) **विनिर्माण और सेवाएं**: टियर 2 और 3 शहरों पर ध्यान देने के साथ एक सक्षम इकोसिस्टम बनाना; (ii) **एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार**: ग्रामीण गैर कृषि और शहरी अवसर; और (iii) **हरित अर्थव्यवस्था**: नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल।

(ग) हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून, 2025 तक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने हेतु ज्ञान, अनुसंधान और संस्थागत क्षमताओं में अंतर को पाटना था। सभी आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और राज्य कृषि विभागों के अधिकारियों ने 728 जिलों में इस अभियान का नेतृत्व किया और 2,170 टीमों द्वारा संचालित 60,840 कार्यक्रमों के माध्यम से 1.4 लाख गाँवों के 1.34 करोड़ किसानों तक पहुँचकर ग्रामीण आबादी, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को सक्रिय रूप से लाभान्वित किया। इस अभियान ने जमीनी स्तर पर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे किसानों के नवाचार, शोध योग्य मुद्दे और भविष्य की पहलों और नीति नियोजन के लिए कार्रवाई योग्य सुझाव सामने आए।

***